PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 257
दि. 20.06.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शहीद दिवस रैली पर घिरा तृणमूल नेतृत्व, हाईकोर्ट के नोटिस से बढ़ी ममता और अभिषेक की मुश्किलें

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव Abhishek Banerjee को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। मामला तृणमूल कांग्रेस की बहुचर्चित शहीद दिवस रैली से जुड़ा हुआ है, जिसे पार्टी हर वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजित करती है। आरोप है कि वर्ष 2025 में आयोजित रैली के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की अनदेखी की गई और शहर के महत्वपूर्ण यातायात मार्गों को इस तरह अवरुद्ध किया गया जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कलकत्ता हाईकोर्ट का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और सार्वजनिक सुविधाओं के संरक्षण से भी संबंधित है। अदालत के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि 21 जुलाई 2025 को आयोजित तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के दौरान ऐसे हालात पैदा हुए जिन्होंने न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया। इसी आधार पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति Arijit Banerjee की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने का फैसला किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। अब राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

इस पूरे विवाद की जड़ वर्ष 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में निहित है। उस समय अदालत ने सार्वजनिक सभाओं, राजनीतिक रैलियों और बड़े आयोजनों को लेकर कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को शहर की मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण यातायात मार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत का मानना था कि लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

अपने आदेश में अदालत ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया था कि किसी भी रैली या प्रदर्शन के दौरान सड़क का एक हिस्सा हमेशा आम जनता और वाहनों के आवागमन के लिए खुला रखा जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवाजाही का अधिकार मिलना चाहिए। न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया था कि यदि किसी कार्यक्रम के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसके संबंध में पहले से जनता को सूचित किया जाए ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शहीद दिवस रैली के दौरान इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र, जो शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण यातायात केंद्रों में गिना जाता है, को रैली के दौरान लगभग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था। इससे हजारों यात्रियों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आरोप यह भी है कि कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था इतनी प्रभावित हुई कि लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल ट्रैफिक जाम या प्रशासनिक चूक तक सीमित नहीं है। यदि अदालत यह मानती है कि उसके पूर्व आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है, तो इसे न्यायिक आदेशों की अवमानना के रूप में देखा जा सकता है। यही कारण है कि अदालत ने मामले को प्राथमिक स्तर पर ही गंभीरता से लिया और संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किया।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शहीद दिवस रैली का विशेष महत्व है। तृणमूल कांग्रेस हर वर्ष 21 जुलाई को इस कार्यक्रम का आयोजन करती है और इसे पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में गिना जाता है। राज्य के विभिन्न जिलों से लाखों कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में भाग लेने के लिए कोलकाता पहुंचते हैं। पिछले कई वर्षों से यह आयोजन तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का प्रमुख मंच रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से व्यापक राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है।

विपक्षी दल पहले भी इस प्रकार के बड़े आयोजनों के दौरान यातायात अव्यवस्था और नागरिकों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि आम जनता के दैनिक जीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल का कहना रहा है कि इतने बड़े आयोजनों में कुछ अस्थायी व्यवधान स्वाभाविक होते हैं और प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं करने का प्रयास करता है।

अब जबकि मामला अदालत के समक्ष पहुंच चुका है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का नोटिस किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने का अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि यह संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालेगी। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने लेकर आया है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन और जनसभाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन साथ ही नागरिकों के आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को भी सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। न्यायालयों ने समय-समय पर इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस नोटिस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी आगामी सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। वहीं विपक्ष इस घटनाक्रम को सरकार और तृणमूल नेतृत्व के लिए बड़ा झटका बता रहा है।

आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अदालत की आगामी सुनवाई में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यदि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और अदालत को लगता है कि उसके आदेशों का उल्लंघन हुआ है, तो इसके दूरगामी राजनीतिक और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि संबंधित पक्ष अदालत को संतुष्ट करने में सफल रहते हैं तो विवाद का स्वरूप बदल सकता है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस कदम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जारी नोटिस ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। अब सबकी नजरें 3 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई होगी और यह स्पष्ट हो सकेगा कि शहीद दिवस रैली से जुड़ा यह विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने खेरगाम तहसील के पाणीखड़क गांव में रात्रिसभा आयोजित कर ग्रामीणजनों के साथ आत्मीय संवाद किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित निवारण के लिए स्थानीय प्रशासन को दिए निर्देश

गांधीनगर : नवसारी जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने खेरगाम तहसील के आछवणी गांव में वृक्षारोपण कर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण के विस्तार में सहभागी होने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को प्रेरक संबोधन देते हुए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस युग में यदि हमें अपनी धरती माता को बचाना है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खेती में प्राकृतिक पद्धतियां अपनाने से ही जमीन की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और लगाए गए पौधों की अपनी संतान की तरह देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी की बूंद-बूंद का संग्रहण और प्रत्येक नागरिक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया एक छोटा-सा कदम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधे की देखभाल न करना और उसे सूखने देना भ्रूण हत्या के जैसा पाप है। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रामीण स्तर से शुरू हुई यह जनजागरूकता ही सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के निर्माण का आधार बनेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे, तभी हम अपने जीवन और संस्कृति को टिकाए रख पाएंगे। कोरोना काल के संकट समय की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुदरत ने हम सभी को बड़ा सबक सिखाया है कि हमारे पास चाहे कितना ही धन या वैभव क्यों न हो, लेकिन यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हमें हमारा शरीर छोड़ना होगा और इसमें किसी का कुछ नहीं चलेगा।

मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर नागरिकों से संभल जाने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने पानी और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूक होने की अपील की। जल संचय के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण हो और वह पानी से भरे रहें, इसके लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संवेदनशील दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण अभियान को संवेदना के साथ जोड़ा है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक से अपनी माता के नाम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को और गति देते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बरगद का पौधा लगाया और ग्रामीणों से यह अपेक्षा व्यक्त की कि वे इस पौधे का पोषण और देखभाल करके इसे विशाल और छायादार बनाएंगे। साथ ही, ग्रामीणों के सहयोग से कुल 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में नीम, पीपल, बरगद, बेल, काजू, कदंब, सेवन और बहेड़ा सहित 28 प्रजातियों के कुल 1600 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण तथा हरित आवरण के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह आने वाली पीढ़ी के लिए स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण के निर्माण का एक जरिया बनेगा। उल्लेखनीय है कि वन विभाग ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत राज्य में 5.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जिवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, परियोजना प्रशासक श्री स्वप्निल एम सिसले, उप वन संरक्षक सुश्री उर्वशी प्रजापति सहित कई पदाधिकारी, अधिकारी, स्थानीय अग्रणी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

गुजरात सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप्स और उभरती प्रौद्योगिकियों पर उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया

एमएसएमई, सप्लाई चेन और इकोसिस्टम एनेबलर्स पर रहा फोकस; स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाकर नवाचार को गति देने पर जोर

गांधीनगर, 19 जून : गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई और स्टार्टअप्स के एकीकरण को तेज़ करने के उद्देश्य से गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) में 'इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन डिफेंस' विषय पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया।

इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, सैन्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वालिटी डेवलपमेंट सेंटर (EQDC) सहित विभिन्न संस्थानों ने भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में सक्षम स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए एक साझा रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की।

आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए EQDC के निदेशक एवं गुजरात सरकार के संयुक्त तकनीकी सलाहकार डॉ. नील श्रीमाली ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा। उन्होंने कहा, "पहले सरकार पूरी तरह रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और DRDO पर निर्भर थी। अब यह क्षेत्र खुल चुका है और सरकार स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों को स्टार्टअप्स के समक्ष मौजूद चुनौतियों और बाधाओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों और लाभों पर प्रकाश डालते हुए उद्योगों से उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एकजुटता और सहयोग का आह्वान रहा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) में निदेशक एयर कमोडोर डॉ. जयंत कुमार साहू (सेवानिवृत्त) ने स्टार्टअप्स को "प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग" की भावना के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "रक्षा क्षेत्र की 'वैली ऑफ डेथ' जैसी चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर बढ़ना होगा।" उनके अनुसार, "यदि एक संस्था प्रिसीजन हार्डवेयर पर कार्य करे और दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले तो हम एक मजबूत, एकीकृत और स्वदेशी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं।"

पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव रहित प्रणालियाँ और उन्नत सामग्रियों जैसी अगली पीढ़ी की सैन्य क्षमताओं का विकास छोटे और नवाचारी उद्यमों की चुस्ती और क्षमता पर निर्भर करता है। वक्ताओं ने कहा कि नवाचारों को प्रोटोटाइप चरण से आगे बढ़ाकर सीधे सैन्य आपूर्ति प्रणाली तक पहुंचाने के लिए नियामकीय एवं परीक्षण संबंधी बाधाओं को दूर करना प्राथमिक आवश्यकता है।

कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी में 31 रक्षा स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इनमें एयरोशील्ड, बजरंग यूएवी, क्लोविन सिक्योरिटी, ड्रोनलैब टेक्नोलॉजीज़, ओमस्पेस रॉकेट, ऑर्बिट स्पेस और प्राइम यूएवी सहित कई स्टार्टअप्स शामिल थे। इन कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के दौरान प्रतिभागियों ने EQDC के साथ तकनीकी परीक्षण ढांचों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की।

राज्य के उद्योग एवं खनन विभाग के सहयोग से संचालित EQDC वर्तमान में इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC), भारतीय वायु सेना तथा ओएनजीसी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को नियमित सेवाएं प्रदान कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रयास गुजरात को देश के अग्रणी रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी की खेरगाम तहसील के आछवणी गांव में वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

- लगाए गए पौधे की देखभाल न करना और उसे सूखने देना भ्रूण हत्या के जैसा पाप है : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत
- प्रकृति का संरक्षण ही जीवन और संस्कृति के विकास का आधार : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- ग्रामीणों के सहयोग से 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में नीम, पीपल, बरगद, बेल, काजू, कदंब, सेवन और बेहड़ा सहित 28 प्रजाति के कुल 1600 पौधों की बुवाई
- वन विभाग का 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पूरे राज्य में 5.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

गांधीनगर : नवसारी जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने खेरगाम तहसील के आछवणी गांव में वृक्षारोपण कर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण के विस्तार में सहभागी होने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को प्रेरक संबोधन देते हुए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस युग में यदि हमें अपनी धरती माता को बचाना है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खेती में प्राकृतिक पद्धतियां अपनाने से ही जमीन की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और लगाए गए पौधों की अपनी संतान की तरह देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी की बूंद-बूंद का संग्रहण और प्रत्येक नागरिक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया एक छोटा-सा कदम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधे की देखभाल न करना और उसे सूखने देना भ्रूण हत्या के जैसा पाप है। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रामीण स्तर से शुरू हुई यह जनजागरूकता ही सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के निर्माण का आधार बनेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे, तभी हम अपने जीवन और संस्कृति को टिकाए रख पाएंगे। कोरोना काल के संकट समय की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुदरत ने हम सभी को बड़ा सबक सिखाया है कि हमारे पास चाहे कितना ही धन या वैभव क्यों न हो, लेकिन यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हमें हमारा शरीर छोड़ना होगा और इसमें किसी का कुछ नहीं चलेगा।

मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर नागरिकों से संभल जाने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने पानी और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूक होने की अपील की। जल संचय के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण हो और वह पानी से भरे रहें, इसके लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संवेदनशील दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण अभियान को संवेदना के साथ जोड़ा है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक से अपनी माता के नाम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को और गति देते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बरगद का पौधा लगाया और ग्रामीणों से यह अपेक्षा व्यक्त की कि वे इस पौधे का पोषण और देखभाल करके इसे विशाल और छायादार बनाएंगे। साथ ही, ग्रामीणों के सहयोग से कुल 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में नीम, पीपल, बरगद, बेल, काजू, कदंब, सेवन और बहेड़ा सहित 28 प्रजातियों के कुल 1600 पौधे लगाए गए।

वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण तथा हरित आवरण के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह आने वाली पीढ़ी के लिए स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण के निर्माण का एक जरिया बनेगा। उल्लेखनीय है कि वन विभाग ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत राज्य में 5.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जिवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, परियोजना प्रशासक श्री स्वप्निल एम सिसले, उप वन संरक्षक सुश्री उर्वशी प्रजापति सहित कई पदाधिकारी, अधिकारी, स्थानीय अग्रणी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

संपादकीय

हद से ज़्यादा सख्ती से बचे सरकार

मई महीने में नीट प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार अति- सतर्कता के मूड में नजर आ रही है। लीक प्रकरण के पश्चात निशाने पर आने के बाद सरकार कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। इसी कड़ी में चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाम लगाने के निर्णय को लेकर विवाद अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये संघर्ष कर रही है। हकीकत यह है कि मई में प्रश्नपत्र लीक होने से मची अफरातफरी और विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आने के बाद केंद्र सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। निस्संदेह, इस परीक्षा में आयोजक एजेंसियों की विश्वसनीयता और बीस लाख से ज्यादा प्रतिभागियों का भविष्य दांव पर लगा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाओं को लेकर नीट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एटीए द्वारा परीक्षार्थियों का भरोसा फिर से कायम करने की कवायद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में रविवार को होने वाली नीट की पुनःपरीक्षा से ठीक पहले, सरकार का चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कुछ अवधि के लिये प्रतिबंध लगाना, अति सतर्कता को ही दर्शाता है। सरकार के इस अतिरेक सावधानी वाले रवैये को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने इस कदम का पुरजोर बचाव किया है। सरकार की दलील है कि इस क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म का बॉट इंफ्रास्ट्रक्चर लीक हुई सामग्री का तेजी से बड़े पैमाने पर प्रसार करने में मददगार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में देशवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूरे प्लेटफॉर्म को कुछ दिनों के लिये ब्लॉक करने से आनुपातिकता और प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लोगों का मानना है कि सतर्कता, सावधानी और तंत्र में सुधार कर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निस्संदेह, यदि किसी आपराधिक नेटवर्क द्वारा ऐप विशेष के दुरुपयोग की वजह से, उसके असली यूजर्स को परेशानी होती है तो इससे देश में गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार दलील दे रहे हैं कि अगर किसी बड़ी परीक्षा हेतु टेलीग्राम की सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं तो भविष्य में किसी अन्य मुद्दे पर दूसरे ऐप के विरुद्ध कार्रवाई को भी तार्किक ठहराया जा सकता है। फिर सत्ताधीशों को किसी अन्य ऐप पर अंकुश लगाने का अवसर बार-बार मिल सकता है। सरकारें कानून-व्यवस्था को खतरा बता कर, कार्रवाइयों को जायज ठहरा सकती हैं। तभी मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने पूछा है कि 150 मिलियन यूजर्स के अधिकारों में कटौती कैसे की जा सकती है? आलोचक सरकार के रवैये को सिस्टम की विफलता बता रहे हैं। दलील है कि कोई भी प्रश्न पत्र तभी लीक होता हैं, जब परीक्षा से जुड़े कुछ अंदरूनी लोग नकल कराने वाले गिरोहों से मिल जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने से समस्या खत्म नहीं होती है। इस प्रतिबंध के बाद यूजर्स आसानी से वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या दूसरे ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। निस्संदेह, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गलत कामों को अंजाम देने के लिये किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से तकनीक की उपादेयता को खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर देश के दूर-दराज के इलाकों में प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिये भारतीय वायु सेना को तैनात करने को एक सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था को फुलप्रुफ बनाने की कवायद के रूप ध्यान तो खींचता है, लेकिन किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं बन सकता । निस्संदेह, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और छात्रों का भरोसा जीतने के लिये सरकार द्वारा पूरी परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किसी भी सरकार के लिये यही बेहतर होगा कि वह अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग बेहद पारदर्शी तरीके से और कम से कम करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका गलत इस्तेमाल न हो सके।

दलीय टूट-फूट के सवालों से मुठभेड़ जरूरी

> "निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के गठन की बुनियाद उनका राजनैतिक और सामाजिक विचार और सिद्धांत होता है। इसके बावजूद लगातार महंगी होती चुनाव प्रक्रिया ने विचारधारा की राजनीति को पीछे खिसका दिया है। विचारधारा की दुहाई तभी तक दी जाती है, जब तक उसकी राह में धन बल या बाहुबल नहीं आता, जब तक कि सत्ता उससे दूर रहती है।

डॉक्टर लोहिया ने कहा तो था समाजवादियों से, लेकिन लगता है कि उनकी बात आज के विपक्षी दलों ने ज्यादा शिद्दत से मान ली है। लोहिया ने कहा था, सुधरो या टूट जाओ। लोहिया की इस अपील को उनके समाजवादी चेलों ने तो माना ही, अब गैर समाजवादी अनुयायी भी स्वीकार कर चुके हैं। चार मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ी टूट उस ममता की पार्टी में हुई, जिन्हें राजनीतिक मैदान का योद्धा माना जाता था। जो झुकना नहीं जानतीं। पहले उनके 80 में से 53 विधायक टूट गए और विधानसभा में उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया। इसके बाद लोकसभा के उनके 29 में से बीस सांसद भी टूट गए। दिलचस्प यह है कि उन्होंने एक अनाम-सी पार्टी नेशनल सिटिजन्स पार्टी में अपना विलय कर लिया। ममता की राह पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी सांसद चल पड़े हैं और हो सकता है कि इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक उनके नौ में से छह लोकसभा सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के धनुष पर तीर चढ़ा रहे होंगे। सुगबुगाहट तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के संसदीय दल में भी टूट-फूट की दिख रही है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट की भविष्यवाणी जता दी है। भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी दल-बदल होते रहे हैं। हरियाणा में तो तकरीबन पूरा विधायक दल ही दूसरे दल में समा गया था। उसी के बाद से दलबदल के लिए भारतीय राजनीति में 'आयाराम गयाराम' का मुहावरा ही चल पड़ा था। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद जिस तरह दल-बदल या दलों में टूटफूट हो रहा है, वह अप्रत्याशित है। इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों में भगदड़ पहले नहीं हुई थी। पहले किसी एक या दो दल में ऐसा होता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी विरोधी दलों को दल-बदल या टूट-फूट वाली छूत की बीमारी लग गई है। इस प्रभावित दल इस टूट-फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी टूटने वाले नेताओं को मोटी रकम का लालच दे रही है। उनका यह भी आरोप है कि संवैधानिक सुधारों के लिए चूंकि बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, इसलिए वह धन और बाहुबल का लालच देकर दलों को तोड़ रही है। एक बारगी मान भी लें कि बीजेपी की शह पर ये टूट-फूट हो रही है तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर राजनीतिक दलों ने कैसे नेताओं को अपना सांसद या विधायक बनाने के लिए चुना है? क्या उनके चयन में कोई गलती रही? सवाल यह भी उठता है कि जो टूट रहे हैं, क्या सांसद या विधायक बनाने को लेकर जब उनका चयन किया जा रहा था, तो उनकी कौन की खासियत देखी गई थी? क्या दल के प्रति न उनकी निष्ठा, उनके चरित्र आदि का ध्यान नहीं रखा गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या बाहुबल या धन बल ही उनके चयन की बड़ी योग्यता मानी गई। इन सवालों का ईमानदारी से जवाब प्रभावित दल भले ही नहीं दे, लेकिन यह छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय राजनीति में संसद या विधानसभा में नुमाइंदगी के लिए दलीय निष्ठा की बजाय दूसरे कारकों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें चुनाव जीतने की क्षमता, चुनाव में खर्च करने की सामर्थ्य और जरूरत बड़ने पर पार्टी के लिए धन और बाहुबल के साथ खड़ा होने की शक्ति भी देखी जाती है। कई बार तो सिर्फ पैसे के दम पर ही टिकट हासिल कर लिए जाते हैं। यही वजह है कि मौका मिलते ही ये नेता अपनी निष्ठा बदलने में देर नहीं लगाते।

निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के गठन की बुनियाद उनका राजनैतिक और सामाजिक विचार और सिद्धांत होता है। इसके बावजूद लगातार महंगी होती चुनाव प्रक्रिया ने विचारधारा की राजनीति को पीछे खिसका दिया है। विचारधारा की दुहाई तभी तक दी जाती है, जब तक उसकी राह में धन बल या बाहुबल नहीं आता, जब तक कि सत्ता उससे दूर रहती है। अगर विचारधारा से विचलन के बाद सत्ता आती दिखती है तो राजनीतिक दल और नेता भी अपनी उस विचारधारा को कुछ वक्त के लिए ताक पर रख देते हैं। सिद्धांत और निष्ठाएं भी तब तक के लिए टाल दी जाती हैं। जब दलीय आधार पर ऐसा होता है तो निजी स्तर पर किसी सांसद और विधायक को आर्थिक या सत्ता में भागीदारी का मौका मिलेगा तो वह क्यों न टूटेगा। सवाल यह है कि जब दल और उसका अगुआ ही अपनी निष्ठा और विचारधारा को सत्ता के लिए किनारे रख देगा तो मौका मिलने पर उसका सांसद और विधायक ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के संसदीय दल में बिखराव की बड़ी वजह सत्ता के लिए पार्टी के सिद्धांतों से समझौता और कांग्रेस का साथ लेना रहा है।

टूट रहे सांसदों को लेकर आरोप लगाने वाले दलों को भी सोचना होगा कि आखिर उन्होंने किस तरह के लोगों को चुना? सवाल यह है कि जब पैसे लेकर टिकट दिए जाएंगे, जब दल और विचारधारा की निष्ठा के बजाय चुनावी टिकट हासिल करने के अन्य कारण होंगे तो फिर इस प्रक्रिया से चुनकरआए सांसदों और विधायकों की खरीद-बिक्री पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? कैसे उन्हें दलीय निष्ठा के प्रति बांधे रखा जा सकता है। दलीय टूट-फूट का अभी कोई बड़ा नुकसान भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा हश्र लोक विश्वास के दरकने के रूप में दिख सकता है। आज का मतदाता बहुविध सूचनाओं के तमाम स्रोतों से लैस है। उसकी राजनीतिक समझ पहले के मीडिया क्रांति केदौर के पहले के मतदाताओं की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित है। उसका सामान्य ज्ञान कमजोर भले ही हो सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें आ रहे निष्ठागत बदलावों की पृष्ठभूमि को वह समझ रहा है। ऐसे में उसका भरोसा मौजूदा राजनीतिक तंत्र से चूक सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसका भरोसा टूटना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। दल बदलने वाले अपने प्रतिनिधि के बारे में वह सवाल उठा सकता है कि उसने जिस सोच के साथ उसे वोट दिया, उसका प्रतिनिधि उस सोच के साथ गद्दारी कर रहा है। कई बार स्थानीय कारणों के साथ ही अपनी वैचारिक निष्ठा के चलते भी अपना मत देता है। हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल विशेष को बड़ा समर्थन मिला हो, लेकिन उसी दल विशेष के किसी स्थानीय प्रतिनिधि को स्थानीय निष्ठाओं, जरूरतों और कारकों के साथ ही वैचारिक कारणों से मतदाताओं का समर्थन नहीं मिलता। मान लेते हैं कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर किसी दल विशेष को भारी समर्थन मिला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसके ठीक उलट किसी अन्य दल या उसके प्रतिनिधि को समर्थन मिला है। इसका मतलब यह है कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करने वाले दल के कार्यक्रमों और योजनाओं की बजाय स्थानीय योजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों की अपनी अलग दृष्टि है, या अपनी अलग चाहत है। स्थानीय मतदाताओं का भरोसा उसे इसी वजह से मिला है। लेकिन उसका प्रतिनिधि अपनी निष्ठा बदल लेता है कि स्थानीय मतदाता खुद को आहत और ठगा हुआ महसूस कर सकता है। चूंकि इन दिनों दलीय टूट-फूट व्यापक स्तर पर हो रही है, इसलिए मतदाताओं में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इसके चलते मतदाता आहत महसूस कर स0कते हैं, विश्वासघात भी मान सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक तंत्र को मतदाताओं के मनमिजाज को इस नजरिए से भी समझना होगा। भारतीय लोकतंत्र को भरोसेमंद बनाने की राह राजनीतिक दलों को ही खोजना होगा। क्योंकि लोहिया की टूटने की अपील के पीछे भी सुधार को खोजना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल संपूर्णता में इस सवाल से मुठभेड़ करने को तैयार हैं?

प्रेरणा

अहंकार की सीढ़ी नहीं, पतन का मार्ग है चापलूसी

राजाओं के दरबार केवल शासन चलाने के केंद्र नहीं होते थे, बल्कि वे ज्ञान, नीति, धर्म और जीवन-दर्शन के भी महत्वपूर्ण मंच होते थे। वहां होने वाली चर्चाएं केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान नहीं करती थीं, बल्कि मानव जीवन के गहरे सत्यों को भी उजागर करती थीं। एक ऐसे ही विद्वतापूर्ण दरबार में घटी घटना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी सदियों पहले थी।

एक दिन एक प्रतापी राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। राज्य के प्रमुख विद्वान, मंत्री, सेनापति और राजगुरु उनके समक्ष उपस्थित थे। राजा का स्वभाव जिज्ञासु था। वे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनके माध्यम से वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे। उस दिन उनके मन में एक विशेष प्रश्न उठा। उन्होंने दरबार में उपस्थित विद्वानों से पूछा, "बताइए, संसार में सबसे अधिक जहरीला और सबसे तेज काटने वाला कौन होता है?"

राजा का प्रश्न सुनते ही दरबार में विचार-विमर्श आरंभ हो गया। प्रत्येक विद्वान अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर देने लगा। एक विद्वान ने कहा कि ततैया सबसे अधिक कष्टदायक होता है। उसका डंक मनुष्य को असहनीय पीड़ा देता है। दूसरे विद्वान ने कहा कि मधुमक्खी का डंक अत्यंत खतरनाक होता है, विशेषकर तब जब वह झुंड में हमला करे। तीसरे ने बिच्छू को सबसे विषैला बताया और चौथे ने सांप का नाम लिया। उसका तर्क था कि सांप के विष से मनुष्य का जीवन कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता है।

राजा ने सभी उत्तर ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि उन्हें अभी भी संतोष नहीं मिला है। उन्हें लग रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर केवल किसी जीव-जंतु तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी दृष्टि राजगुरु की ओर उठाई, जो अब तक शांत भाव से सबकी बातें सुन रहे थे।

राजा ने विनम्रता से कहा, "गुरुदेव, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर आपके पास है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें।"

राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, "राजन, मेरी दृष्टि में संसार के सबसे विषैले दो प्राणी हैं—निंदक और चाटुकार।"

पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। राजा भी चकित हुए। उन्होंने पूछा, "गुरुदेव, क्या कोई मनुष्य सांप या बिच्छू से भी अधिक विषैला हो सकता है?"

राजगुरु मुस्कुराए और बोले, "निश्चित रूप से। सांप और बिच्छू का विष केवल शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन निंदक और चाटुकार का विष मनुष्य के विचारों, व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "निंदक के भीतर ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना का जहर भरा होता है। वह सामने से नहीं, बल्कि पीछे से वार करता है। उसकी वाणी लोगों के मन में भ्रम और अविश्वास पैदा करती है। वह किसी की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर पाता। उसका उद्देश्य केवल दूसरों को छोटा दिखाना होता है। निंदा का विष संबंधों को कमजोर करता है और समाज में कटुता फैलाता है।"

कुछ क्षण रुककर राजगुरु ने कहा, "लेकिन निंदक से भी अधिक खतरनाक चाटुकार होता है।"

यह सुनकर दरबार में उपस्थित लोग और अधिक ध्यान से सुनने लगे।

राजगुरु बोले, "चाटुकार का विष मीठा होता है। वह व्यक्ति के सामने इतनी प्रशंसा करता है कि उसे अपनी वास्तविकता दिखाई देना बंद हो जाती है। वह हर दोष को गुण और हर गलती को उपलब्धि बताने लगता है। धीरे-धीरे मनुष्य अपने दोषों को पहचानने की क्षमता खो देता है।"

उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति निरंतर झूठी प्रशंसा सुनता है तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। उसे लगता है कि वह जो भी कर रहा है, वही सही है। ऐसी स्थिति में वह सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं करता और यही उसके पतन की शुरुआत होती है।

राजगुरु ने कहा, "इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक शक्तिशाली राजा अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने आसपास मौजूद चाटुकारों के कारण नष्ट हुए। चाटुकार कभी सत्य नहीं बोलता। उसका उद्देश्य केवल अपना लाभ प्राप्त करना होता है। वह व्यक्ति को ऐसी कल्पनाओं में उलझा देता है कि वह वास्तविकता से दूर हो जाता है।"

उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, "जो व्यक्ति आपकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है, वह आपका सच्चा मित्र है। जो आपकी कमियों को छिपाकर केवल प्रशंसा करता है, वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा मित्र कभी-कभी कड़वा सत्य बोलता है, जबकि चाटुकार हमेशा मीठा झूठ बोलता है।"

राजा अब राजगुरु की बातों का गूढ़ अर्थ समझने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि नेतृत्व केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सही सलाह को स्वीकार करने की क्षमता का भी नाम है। यदि कोई शासक केवल प्रशंसा सुनना पसंद करने लगे तो उसके निर्णयों की गुणवत्ता गिरने लगती है। वह वास्तविक समस्याओं को समझ नहीं पाता और अंततः स्वयं तथा अपने राज्य दोनों को संकट में डाल देता है।

राजगुरु ने आगे कहा, "मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उसका अहंकार होता है। और अहंकार को सबसे अधिक पोषण चापलूसी से मिलता है। जिस दिन व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाती है, उसी दिन उसके विकास की गति रुक जाती है। क्योंकि सीखना वहीं बंद हो जाता है जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझने लगता है।"

दरबार में बैठे सभी लोग अब गंभीर चिंतन में डूब चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह शिक्षा केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। चाहे वह शासक हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो या सामान्य नागरिक, हर किसी को अपने आसपास ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उसे सच बताने का साहस रखें।

राजा ने अंत में कहा, "आज मैंने जाना कि सबसे बड़ा विष वह नहीं जो शरीर को नष्ट करे, बल्कि वह है जो विवेक को नष्ट कर दे। निंदा मनुष्य को दुख देती है, लेकिन चापलूसी उसे अंधा बना देती है। इसलिए हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो सत्य बोलते हैं, भले ही उनका सत्य कभी-कभी कड़वा लगे।"

उस दिन के बाद राजा ने अपने दरबार की व्यवस्था में परिवर्तन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के हित से जुड़ी बातों में केवल सत्य और तथ्य प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने ऐसे लोगों को अधिक महत्व दिया जो ईमानदारी से सलाह देते थे और चाटुकारों से दूरी बनानी शुरू कर दी।

यह कथा हमें एक अमूल्य शिक्षा देती है। जीवन में सफलता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सफलता के बाद विनम्र बने रहना। झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सत्य मान लेना विनाश का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति आलोचना से सीखता है और चापलूसी से बचता है, वही निरंतर प्रगति करता है। इसलिए हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि सत्य विकास का मार्ग दिखाता है जबकि चापलूसी पतन की ओर ले जाती है।

भारतीयता कमजोर होगी सद्भाव पर आंच से

युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज़ समझने वाली बात में अब एक बात और जुड़ गयी है– अब चुनाव में भी सब कुछ सही मान लिया गया है। भले ही हमने अपने संविधान में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास जताया हो, पर धर्म की दुहाई देकर राजनीतिक स्वार्थ साधने के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनावों में हमने देखा कि धर्म की राजनीति करने वाले हमारे राजनेताओं को ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। असम और बंगाल में यह प्रकृति खुलकर सामने आयी। खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे गये, और धर्म के नाम पर वोट देने वालों की भी कमी नहीं रही।

बहुत पुरानी बात नहीं है जब भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निस्संकोच यह कहा था कि उन्हें, यानी उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी इस बात के पीछे का गणित बहुत स्पष्ट था। देश में मुसलमानों की आबादी लगभग बीस प्रतिशत है। यदि शेष अस्सी प्रतिशत में से पचास-साठ प्रतिशत मतदाता भी धर्म के आधार पर वोट देते हैं तो धर्म की राजनीति करने वालों की विजय सुनिश्चित है। पिछले सात-आठ दशकों में देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को धर्म के नाम पर वोट देने के लिए उकसाने की कोशिशों से कौन अपरिचित है? पर यह भी एक वास्तविकता है कि इस देश के बहुसंख्यकों ने सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। इन कोशिशों को असफल बनाना देश के बेहतर कल की एक प्रमुख शर्त है।

हमारे संविधान-निर्माता इन कोशिशों के खतरों को अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समता और न्याय के साथ भाई-चारे को जोड़ना ज़रूरी समझा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि भारत सामाजिक जनतंत्र को स्थापित करने में विफल रहता है तो हमारा राजनीतिक जनतंत्र भी बिखर जायेगा। संविधान-सभा में 25 नवम्बर, 1949 के अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बात बड़ी स्पष्टता और गंभीरता के साथ समझायी थी। उन्होंने कहा था कि जनतंत्र के चारों आधारों—समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता– का बने रहना जनतांत्रिक भारत के अस्तित्व की शर्त है। वे यह मानते थे कि यदि इन चारों में से किसी एक को भी अपनी जगह से हटाया गया तो जनतंत्र का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

उन्होंने कहा था, 'स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, न ही समानता को स्वतंत्रता से दूर किया जा सकता है। इसी तरह स्वतंत्रता और समानता को भाई-चारे से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि समानता नहीं रही तो 'बहुतों' पर 'कुछ' को वरीयता मिल जायेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता का मतलब व्यक्ति की पहल करने की क्षमता को नकारना होगा।'

जहां तक भाई-चारे का सवाल है इसका सीधा-सा मतलब है सभी भारतीयों का एक-दूसरे से जुड़ा होना और जुड़ा रहना। उन्होंने इसके साथ ही यह कहना भी ज़रूरी समझा था कि इसके बिना स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता। संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर इस विचार को रेखांकित करने वाले अकेले नहीं थे। और भी कइयों ने स्वतंत्र जनतांत्रिक भारत में भाई-चारे की आवश्यकता और महत्ता को रेखांकित किया था। वे सब इस बात को मानते थे कि भाई-चारा ही वह गोंद है जो भारतीयों को जोड़े रखेगी। बहुधर्मीय, बहुजातीय और बहुभाषी भारत को आपसी भाई-चारे की भावना ही जोड़े रख सकती है। आज़ादी की अब तक की यात्रा में यदि हम सब एक साथ आगे बढ़ पाये हैं तो उसका श्रेय भी भाई-चारे को समता, स्वतंत्रता और न्याय जितना महत्व देने को जाता है। यह भाई-चारा हमारे संविधान-निर्माताओं के लिए कोई मोहक कल्पना नहीं था, एक ठोस आधार था देश के भविष्य का। सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो वह समय देश में भारी उथल-पुथल का था। विभाजन की त्रासदी को झेल रहा था देश, सांप्रदायिकता की आंच भी जब-तब सिर उठा रही थी। उस माहौल में भाई-चारे के दार्शनिक विचार को जनता के मन और मस्तिष्क तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ हमारे संविधान-निर्माता यह काम करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर बंगाल में महात्मा गांधी अपनी 'एक व्यक्ति की सेना' के सहारे सांप्रदायिकता की आग बुझाने का काम कर रहे थे।

यह तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस दिन राजधानी दिल्ली में यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा फहराया जा रहा था, महात्मा गांधी दिल्ली से हज़ारों मील दूर बंगाल में थे। सांप्रदायिकता की आग के घावों पर मरहम लगा रहे थे। गांधी अच्छी तरह समझते थे कि बंधुता को जिये बिना देश में सही अर्थों में जनतंत्र नहीं आ सकता। आज इस बात को फिर से समझने की आवश्यकता है कि गांधी ने 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के बजाय कोलकाता (तब कलकत्ता) में रहना ज़रूरी क्यों समझा था। आज फिर उस भाई-चारे को समझने-जीने की आवश्यकता है।

असम, बंगाल जैसे राज्यों में हाल के चुनावों में हमने देखा है कि किस तरह सांप्रदायिकता की आंच को हवा देने का काम हुआ है। धर्म के नाम पर वोट मांगना, और वोट दिया जाना, देश के संविधान को नकारना, उसका अपमान करना है। पर यह काम हुआ। हमारे संविधान-निर्माताओं ने धर्म के आधार पर वोटों के बंटवारे को नकार कर स्पष्ट कर दिया था कि धर्म-निरपेक्ष, जनतांत्रिक भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य ही है कि आज फिर देश में कुछ तत्व इस राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं।

अभियान

जब भगवान स्वयं निकलते हैं भक्तों के द्वार: जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत महिमा और रस्सी खींचने का दिव्य रहस्य

भारत की सनातन परंपराओं में अनेक ऐसे उत्सव हैं जो केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और मानवता के विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इन उत्सवों में ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्थान अत्यंत विशिष्ट और पवित्र माना जाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के मिलन का ऐसा दिव्य अवसर है जिसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और भावनाएं समाहित होती हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलने वाली यह यात्रा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के रथों का दर्शन करते हैं।

रथ यात्रा का सबसे आकर्षक और आध्यात्मिक पक्ष वह क्षण होता है जब लाखों भक्त भगवान के रथ की विशाल रस्सियों को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस दृश्य को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भावविभोर हो उठता है। लोगों की आंखों में श्रद्धा, हाथों में भक्ति और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता दिखाई देता है। अनेक श्रद्धालु तो वर्षों तक इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं ताकि उन्हें भगवान के रथ की रस्सी छूने या उसे खींचने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।

सनातन मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना जाता है। विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ रथ की रस्सी खींचता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिर से बाहर निकलकर जनता के बीच आते हैं। यही कारण है कि इस अवसर पर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति के सभी भेद मिट जाते हैं। राजा और रंक, अमीर और गरीब, सभी एक ही रस्सी को पकड़कर भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं।

जगन्नाथ संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। जब भगवान मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर सड़क पर आते हैं तो यह संदेश देते हैं कि उनकी कृपा किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है। वे सभी के भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने का समान अधिकार है। रथ यात्रा इसी समरसता और समानता का जीवंत प्रतीक बन जाती है।

भगवान जगन्नाथ का रथ 'नंदीघोष' नाम से प्रसिद्ध है। यह रथ अपनी भव्यता और विशालता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 विशाल पहिए लगे होते हैं। भगवान बलभद्र के रथ को 'तलध्वज' कहा जाता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम 'दर्पदलन' या 'देवदलन' है, जिसमें 12 पहिए लगाए जाते हैं। इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नए सिरे से किया जाता है। यह कार्य अत्यंत पवित्र माना जाता है और विशेष परंपराओं तथा वैदिक विधानों के अनुसार संपन्न किया जाता है।

रथ निर्माण के लिए विशेष प्रकार की लकड़ियों का चयन किया जाता है। सैकड़ों कारीगर कई महीनों तक अथक परिश्रम करके इन रथों को तैयार करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सदियों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही रथों का आकार, स्वरूप और निर्माण प्रक्रिया आज भी वैसी ही है जैसी प्राचीन काल में थी। यह परंपरा भारतीय संस्कृति की निरंतरता और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

रथ यात्रा के दिन जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया जाता है तो पूरे पुरी में उत्सव का वातावरण छा जाता है। शंखध्वनि, घंटों की गूंज, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और 'जय जगन्नाथ' के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। लाखों श्रद्धालु भगवान के एक दर्शन के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही भगवान अपने रथों पर विराजमान होते हैं, भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं।

रथ यात्रा की एक विशेष परंपरा 'छेरा पहंरा' भी है। इस परंपरा में पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से भगवान के रथों की सफाई करते हैं। यह परंपरा इस सत्य का प्रतीक है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं। चाहे कोई राजा हो या सामान्य व्यक्ति, ईश्वर की दृष्टि में सभी सेवक हैं। भारतीय संस्कृति में विनम्रता और सेवा के महत्व को दर्शाने वाली यह परंपरा विश्वभर के लोगों को आकर्षित करती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भगवान का गुंडिचा मंदिर जाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मुख्य मंदिर से निकलकर लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। वहां वे कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर 'बहुदा यात्रा' के माध्यम से वापस श्रीमंदिर लौटते हैं।

इस परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। भगवान का अपने भक्तों के बीच आना यह दर्शाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं। वे अपने भक्तों के सुख-दुख में सहभागी बनते हैं और उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि वे सदैव उनके साथ हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को भगवान और भक्त के बीच प्रेम तथा निकटता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है।

धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचना आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। रथ को मानव शरीर और भगवान को आत्मा का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त रथ को खींचते हैं तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि वे अपने जीवन को ईश्वर की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का भी संकेत है।

जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। आज दुनिया के अनेक देशों में भी इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूरोप के कई देशों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। विदेशी भक्त भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लेते हैं जितने भारतीय श्रद्धालु। यह भगवान जगन्नाथ की सार्वभौमिकता और उनके संदेश की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

समय के साथ अनेक परंपराएं बदल गईं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा आज भी वैसी ही बनी हुई है। आधुनिक युग की व्यस्त जीवनशैली में भी लाखों लोग अपने कार्यों को छोड़कर इस दिव्य उत्सव में शामिल होने पहुंचते हैं। उनके लिए यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है।

जब लाखों हाथ एक साथ भगवान के रथ की रस्सी पकड़ते हैं, तब वहां केवल एक रथ नहीं चलता, बल्कि आस्था, विश्वास, प्रेम और भक्ति का विराट प्रवाह आगे बढ़ता है। उस क्षण हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, चिंताओं और भेदभावों को भूलकर केवल भगवान से जुड़ जाता है। यही वह दिव्य अनुभूति है जो जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया के सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक आयोजनों में स्थान दिलाती है।

इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात सान्निध्य का अवसर है। रथ की रस्सी खींचना केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण का हिस्सा बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं और भगवान के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। उनके लिए यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवनभर संजोकर रखने योग्य आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो उन्हें भगवान के और अधिक निकट ले जाता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

किसानों का आंदोलन कैसे टूटा, इस मुद्दे पर AAP नेता प्रवीण राम, अजीत लोखील और पंकज राणसरिया ने किए खुलासे

▶▶ कांग्रेस ने अपनी विफलता छुपाने के लिए किसानों को गुमराह किया: प्रवीण राम AAP

▶▶ कांग्रेस के कपट और लालच के कारण किसानों का आंदोलन टूटा: प्रवीण राम AAP

▶▶ हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि यदि गांधीनगर रैली की अनुमति मांगी गई थी तो उसे सार्वजनिक करे, और यदि रैली नामंजूर हुई हो तो उसका पत्र भी सार्वजनिक करे : प्रवीण राम AAP

▶▶ हाईटेंशन लाइन के मुद्दे पर भाजपा का विरोध करने की बजाय कांग्रेस ने AAP का विरोध किया: प्रवीण राम AAP

▶▶ कांग्रेस ने गांधीनगर तक जाने की अनुमति मांगी ही नहीं थी: प्रवीण राम AAP

▶▶ कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने के लिए गांधीनगर की बात की लेकिन अनुमति केवल अहमदाबाद के ओगणज तक की ही ली थी: प्रवीण राम AAP

▶▶ अनुमति पत्र में ही लिखा हुआ है कि कांग्रेस की सभा होगी और अमित चावड़ा उपस्थित रहेंगे: प्रवीण राम AAP

▶▶ गुजरात के किसान समझें कि कांग्रेस ने किस हद तक किसानों के साथ कपट करने की कोशिश की: प्रवीण राम AAP

▶▶ कांग्रेस इसी तरह 30 वर्षों से गुजरात के किसानों को ठगती आई है, इसलिए भाजपा सत्ता में बैठी है: प्रवीण राम AAP

▶▶ AAP किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेगी, 27 जून को सुरेंद्रनगर में बड़ी "किसान महापंचायत" आयोजित होगी: प्रवीण राम AAP

▶▶ फरवरी महीने में शुरू हुए आंदोलन में किसान के बेटे के रूप में मैंने पालभाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन दिया था: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ कंटारा से मोरबी की रैली का आयोजन हुआ था, वह रैली भी बीच रास्ते में रोक दी गई थी: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ जेतपुर के किसान स्वामीनारायण गुरुकुल में रात्रि विश्राम करके रात 3:30 बजे रैली के लिए निकलने वाले थे, तो उन्हें सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं निकलने दिया ?: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के नेता अचानक कांग्रेस का खेस पहनकर आए और विवाद खड़ा किया: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ 14 तारीख को सभा की अनुमति मिल जाने के बावजूद भी आखिरी समय तक किसानों को नहीं बताया गया कि रैली गांधीनगर नहीं जाएगी: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ हमने कांग्रेस नेताओं से कहा था कि कांग्रेस के झंडे उतार लो तो किसान सभा में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के झंडे नहीं हटाए: पंकज राणसरिया AAP

▶▶ मैंने हाथ जोड़कर कांग्रेस नेताओं से कहा कि किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास न करें: पंकज राणसरिया AAP

अहमदाबाद/राजकोट/मोरबी/जूनागढ़/गांधीनगर/गुजरातः किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी द्वारा सबूतों के साथ बड़ा खुलासा किया गया। आम आदमी पार्टी के फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम, प्रदेश संगठन मंत्री अजीत लोखील और किसान नेता पंकज राणसरिया ने राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश फ्रंटल अध्यक्ष प्रवीण राम ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ कारणों से आज हमें गुजरात कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी के बारे में सच्चाई जनता के सामने रखना जरूरी हो गया है। हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। हम भाजपा की नीतियों और सरकार के खिलाफ सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन पिछले चार-पांच दिनों से कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। इसलिए आज हमारे लिए यह बताना जरूरी हो गया है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आंदोलन किसने तोड़ा और किन गलत फैसलों के कारण आंदोलन विफल हुआ, यह सबूतों के साथ बताना आवश्यक है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने किसानों को गांधीनगर कूच का ऐलान किया था। किसानों से कहा गया था कि गांधीनगर तक जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधीनगर तक की रैली के लिए आवश्यक अनुमति ली ही नहीं गई थी। यह एक वास्तविक तथ्य है। आज कांग्रेस भूल गई है कि गुजरात में सत्ता किसके पास है। किसानों के मुद्दों पर भाजपा का विरोध करने की बजाय कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध करने में व्यस्त हो गई है। भाजपा से लड़ने की बजाय वे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने में समय बिता रहे हैं। किसानों के हाई टेंशन लाइन के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान किसानों को गांधीनगर तक जाने नहीं दिया गया और अहमदाबाद में ही आंदोलन रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने किसानों को गांधीनगर कूच का ऐलान किया, लेकिन गांधीनगर तक की अनुमति ली ही नहीं। कांग्रेस ने केवल ओगणज तक की रैली के लिए अनुमति ली थी। यदि अनुमति ली ही नहीं हो तो आगे कौन जाने देगा? यह केवल आरोप नहीं है। हमारे पास इसके सबूत हैं। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद द्वारा दी गई अनुमति के दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा है कि रैली शांतिपुरा सर्कल से बोपल सर्कल, शिलज सर्कल, भाडज सर्कल होते हुए ओगणज तक जाएगी। इसके बाद वहां सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। अनुमति दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि सार्वजनिक सभा में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित चावड़ा उपस्थित रहेंगे। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने केवल ओगणज तक की रैली और वहां सभा के लिए अनुमति ली थी, जबकि किसानों को गांधीनगर कूच के नाम पर बुलाया गया था। जब किसानों को समझ में आया कि उन्हें गांधीनगर नहीं ले जाया जाएगा और ओगणज तक की सभा में रोका जा रहा है, तब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। किसानों के सवालों के जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधीनगर जाने की अनुमति नहीं मिली थी।

'आप' नेता प्रवीण राम ने आगे कहा कि सवाल यह है कि यदि अनुमति मांगी ही नहीं गई थी तो मिलेगी कैसे? यदि कांग्रेस ने वास्तव में गांधीनगर तक जाने की अनुमति मांगी थी और सरकार द्वारा इनकार किया गया था, तो उससे संबंधित 'नामंजूरी' का लिखित पत्र जनता और किसानों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अनुमति नहीं मिली थी तो सरकार का नामंजूरी पत्र दिखाइए। केवल मौखिक दावों से काम नहीं चलेगा। यदि कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया है तो उसे यह बात स्वीकार करनी चाहिए। यदि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। झूठे आरोप और भ्रामक बयान देने की बजाय कांग्रेस को तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए और किसानों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो केवल नाश्ते के लिए रुके थे। लेकिन जब किसानों ने सवाल पूछना शुरू किया कि यहां मंच क्यों बनाया गया है? कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं? तो उनके पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। यदि केवल नाश्ते के लिए ही रुकना था तो फिर सार्वजनिक सभा की अनुमति क्यों ली गई? कागज पर सार्वजनिक सभा की अनुमति ली गई थी और उसमें कांग्रेस नेताओं के संबोधन का भी उल्लेख किया गया था। यह स्पष्ट सबूत है कि वहां केवल नाश्ते का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। गुजरात के किसानों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने किस हद तक उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है। किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा करके उनका उपयोग किया गया। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। जब उनकी अपनी गलतियां और विफलताएं सामने आईं, तब उसका दोष आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों पर डालने का प्रयास किया गया। जब किसान नाराज हुए, विरोध व्यक्त किया और सवाल पूछने लगे, तब कांग्रेस ने पूरी घटना का दोष आम आदमी पार्टी और पंकज राणसरिया पर डालने का प्रयास किया। मानो कांग्रेस को दिन-रात केवल आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती हो। यदि आपने किसानों को पहले ही बता दिया होता कि कांग्रेस की सभा में जाना है, कांग्रेस के झंडों और बैनरों वाला कार्यक्रम है, तो किसान अपना निर्णय स्वयं ले सकते थे। लेकिन उन्हें गांधीनगर कूच के नाम पर बुलाया गया और ओगणज के पास ही रोक दिया गया। स्वाभाविक है कि किसानों में आक्रोश फूटे और वे सवाल पूछें। पंकज राणसरिया पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। पंकज राणसरिया कार्यक्रम वाले दिन अचानक उपस्थित नहीं हुए थे। वे किसानों के समर्थन और सहयोग के लिए रैली में शामिल हुए थे। जब किसानों में असंतोष फैला और वे सवाल पूछने लगे, तब पंकज राणसरिया किसानों के साथ खड़े रहे। एक किसान पुत्र के रूप में उन्होंने किसानों की भावनाओं और सवालों को आवाज दी। क्या यह उनका अपराध था?

प्रवीण राम ने आगे कहा कि पंकज राणसरिया के पास इस संबंध में वीडियो सबूत भी हैं। उन वीडियो में वे कांग्रेस नेताओं से कहते हुए दिखाई देते हैं कि यदि यह वास्तव में किसानों का कार्यक्रम है तो कांग्रेस के झंडे और बैनर हटा दीजिए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसा नहीं किया। यदि किसानों का कार्यक्रम खराब करने का इरादा नहीं होता तो किसानों की इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम में विवाद और भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन था। मेरी कांग्रेस को केवल एक सलाह है कि आम आदमी पार्टी का विरोध करने के बजाय भाजपा का विरोध करो। भाजपा के खिलाफ लड़ो। पिछले तीस वर्षों से गुजरात में भाजपा सत्ता में है। किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों के लिए लड़ने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है लेकिन गुजरात के किसानों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। हमने किसानों के अधिकारों के लिए 108 दिनों तक जेल भी काटी है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने किसानों के लिए ऐसा त्याग किया है? कांग्रेस को अभी भी समय रहते समझना चाहिए कि हमारा विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। हम सत्ता में नहीं हैं। गुजरात में सत्ता भाजपा की है। यदि विरोध करना है तो भाजपा का करो, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी उनकी है, आम आदमी पार्टी की नहीं। यदि वास्तव में किसानों के लिए लड़ना है तो भाजपा के खिलाफ लड़ो। हम तो अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। गुजरात के किसानों के अधिकार और न्याय के लिए लड़ने वाले हैं। आगामी 27 तारीख को सुरेंद्रनगर में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आने वाले दिनों में गुजरात के किसानों को न्याय दिलाने के लिए भी हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 14 तारीख को जब रैली के लिए अनुमति मिल गई थी, तब गुजरात के किसानों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? उन्हें यह क्यों नहीं बताया गया कि अनुमति केवल ओगणज तक की है और गांधीनगर तक की नहीं? किसानों को अंधेरे में क्यों रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में गुजरात के किसान कांग्रेस से जरूर मांगेंगे। गुजरात के किसानों को गुमराह करना बंद करें। आंदोलन टूटने के पीछे आपकी गलतियां, आपका लालच और आपकी कपटपूर्ण राजनीति जिम्मेदार है। गुजरात के किसानों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, उसका जवाब आने वाले दिनों में किसान जरूर मांगेंगे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी और किसान नेता पंकज राणसरिया ने कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि फरवरी महीने की दूसरी तारीख को किसानों की पहली रैली का आयोजन पालभाई द्वारा किया गया था। उस समय से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी की टीम ने किसानों के हित में लगातार सहयोग दिया है। 2 फरवरी को मोरबी तक जो ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई थी, उसमें पंकज राणसरिया और हमारी पूरी टीम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुई थी। पालभाई ने हमेशा किसानों के अधिकारों के लिए स्पष्ट रूप से काम किया है और हमने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। इस रैली के दौरान कई स्थानों पर किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई थी। हालांकि मोरबी से तीन किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में पुलिस द्वारा रोक दिया गया था और वहीं किसानों को रोक लिया गया था। उस समय भी किसानों के साथ अन्याय हुआ था। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण रैली आगे नहीं बढ़ सकी थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ नेता केवल थोड़े समय के लिए उपस्थित रहे थे और उसके बाद वे कलेक्टर साहब से मिलने चले गए थे। जबकि किसान वहीं मौजूद रहे और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते रहे। इस पूरी घटना में किसानों के हित की अनदेखी की गई थी, यह स्पष्ट होता है। इसके बाद के चरण में, जेतपुर गांव में 15 तारीख के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने हेतु हम और हमारी टीम विभिन्न गांवों में गए थे। यह कार्यक्रम किसानों के हित में आयोजित किया गया था और इसमें स्थानीय स्तर पर भी व्यापक सहयोग मिला था। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि पिछले चार महीनों से हमारी टीम किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार मैदान में रही है। हर कार्यक्रम में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया गया है। सभी दावों और आरोपों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। मेरा नाम लेकर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा गलत प्रस्तुति की जा रही है, जबकि मेरी कोई सीधी भूमिका न होने के बावजूद मेरा नाम मीडिया और बयानों में लिया जा रहा है। जब रैली का समापन हुआ, उसके बाद मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए, तब भी पालभाई आंबलिया ने मेरा नाम लेने में संकोच किया और आसपास खड़े लोगों से पूछने के बाद मेरा नाम लिया। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि पालभाई से मेरा एक सवाल है। जेतपर गांव और आसपास के गांवों से जो किसान आए थे, उन्हें स्वामीनारायण गुरुओं के स्थान पर रात्रि विश्राम कराया गया था। वहां से इन किसानों को सुबह 3:30 से 4:00 बजे के बीच निकलने की योजना थी, ताकि वे सुबह 9:30 बजे तक शांतिपुरा सर्कल पहुंच सकें। लेकिन हकीकत यह है कि स्वामीनारायण मंदिर परिसर से किसानों को समय पर बाहर निकलने नहीं दिया गया। किसानों को वहीं रोक रखा गया और उन्हें लगभग सुबह 9:30 बजे तक वहां से निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में मेरे पास वीडियो सबूत हैं, जिनमें कांग्रेस के कुछ नेता स्वयं स्वीकार करते दिखाई देते हैं कि किसानों को सुबह 3:30 बजे निकलना था, लेकिन उन्हें समय पर बाहर निकलने नहीं दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में किसानों को पीछे रखा गया और उनके कार्यक्रम की गति को रोका गया। इस बारे में कांग्रेस की ओर से स्पष्टता दी जानी चाहिए कि किसानों को समय पर बाहर क्यों नहीं निकलने दिया गया। हम कांग्रेस से इन सवालों के जवाब मांगते हैं और किसानों को हुई असुविधा के बारे में सच्चाई जनता के सामने रखी जाए, ऐसी मांग करते हैं। शांतिपुरा सर्कल पर अलग-अलग गांवों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मैं भी किसान का बेटा होने के नाते सुबह लगभग नौ बजे वहां पहुंच गया था। इसके बाद साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच अचानक कांग्रेस प्रदेश के कुछ पदाधिकारी और नेता कांग्रेस का खेस पहनकर वहां पहुंचे। इस पूरे आंदोलन के शुरू में यह कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। वहां मौजूद कई लोग किसान प्रतिनिधि के रूप में और किसानों के समर्थन में आए थे। वहां आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी किसानों के हित में उपस्थित थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा स्थिति को अपने पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया और कार्यक्रम को कांग्रेस का स्वरूप देने की कोशिश की गई। मैं भी किसान का बेटा होने के नाते वहां मौजूद था और किसानों के हित में आंदोलन का समर्थन करने आया था, किसी पार्टी की सभा में भाग लेने नहीं। मैंने स्वयं कांग्रेस के कुछ नेताओं से अनुरोध किया था कि यदि यह वास्तव में किसानों का आंदोलन है तो मंच पर लगाए गए कांग्रेस के बैनर और झंडे हटा दिए जाएं, ताकि किसान निष्पक्ष रूप से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। मैंने हाथ जोड़कर भी अनुरोध किया था कि किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास न किया जाए। लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और स्थिति को और अधिक राजनीतिक रंग दिया गया। मेरे पास ऐसा वीडियो भी है जिसमें मैं स्पष्ट रूप से कहता दिखाई देता हूं कि यदि कांग्रेस के बैनर और झंडे हटा दिए जाएं तो किसान कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आगे रख सकते हैं। फिर भी इस बात की अनदेखी की गई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया गया। किसानों को सही जानकारी नहीं दी गई और उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया गया। सुबह मीडिया बाइट में भी यह दिखाया गया कि किसान यहां से गांधीनगर की ओर जाएंगे, जबकि वास्तव में किसानों को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पहले से ही जानकारी थी कि किसानों को गांधीनगर नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी किसानों को अंधेरे में रखा गया।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के खजाने से हजारों करोड़ रुपये के दान और आभूषण गायब होने के आरोपों के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अयोध्या के राम मंदिर से लाखों रुपये की चोरी का मामला अभी ताजा ही है, ऐसे में मथुरा के प्रसिद्ध संत दिनेश फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के खजाने (तोषा खाना) से हजारों करोड़ रुपये के आभूषण और दान की वस्तुएं चोरी हो गई हैं।

यह मामला अयोध्या की स्थिति को दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से दान की गई धनराशि की बड़े पैमाने पर चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने मथुरा मंदिर प्रशासन और तत्कालीन प्रशासकों पर हजारों करोड़ रुपये के दान, सोने-चांदी के आभूषणों और कीमती सामानों की चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए मंदिर के खजाने को निशाने पर ले लिया है। पंडित दिनेश फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले की तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई दशकों बाद जब मंदिर के ऐतिहासिक खजाने (तोशाखाना) को हाल ही में खोला गया, तो सभी लोग अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। आरोप है कि खजाने में रखे बक्से पूरी तरह खाली थे और उनमें राजाओं, महाराजाओं और देश-विदेश के भक्तों द्वारा दान किए गए अनमोल हीरे, रत्न और सोने के आभूषण नहीं मिले। इसके अलावा, मंदिर की कई चल और अचल संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं।

इस प्रकार, मथुरा में "राम मंदिर के दान की चोरी" जैसी घटनाओं के दावों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजनीति और मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो लोगों की ईश्वर में आस्था पर सीधा प्रहार है।

गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार युवाओं को अनैतिक रास्तों की ओर धकेल रहे हैं: इससे गंभीर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शहर में पुलिस की छापेमारी के दौरान, कई युवक-युवतियों को होटलों, गेस्ट हाउसों आदि में अनैतिक धंधे करते हुए पकड़ा गया। लेकिन ये युवतियां इस अनैतिक धंधे में मजबूर और बेबस थीं। इनमें से अधिकतर युवतियां शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं और बेरोजगारी व काम न मिलने के कारण गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए घर में आग जलाना भी मुश्किल है।

ऐसी स्थिति में, जब उनके परिवार को दिन का दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो वे दो वक्त के लिए ऐसे घिनौने धंधों का सहारा लेते हैं। इसमें उनकी गरीबी और मजबूरी अहम भूमिका निभाती है। इसमें खासकर भ्रष्टाचार करके धनवान बने राजनेता और उच्च अधिकारी तथा उनके आश्रित ऐसी मजबूर लड़कियों का पूरा फायदा उठाते हैं। और ऐसे अनैतिक धंधों में पैसा लड़कियों को मनोरंजन का साधन बना देता है। और इस तरह वे उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। इसमें खासकर राजनेता, उद्योगपति और उच्च अधिकारी

ऐसे मनोरंजन के लिए विदेश जाते हैं और मौज-मस्ती करते हैं। देश में बढ़ती नशे की लत के कारण युवा नशे के आदी हो रहे हैं। क्योंकि न काम है, न धंधा है, न नौकरी है और न ही असहनीय महंगाई में जीने का कोई साधन है, ऐसी स्थिति में युवा नशे के आदी होकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।

मौजूदा महंगाई में परिवार चलाना असहनीय हो गया है, जबकि देश में करोड़ों शिक्षित उम्मीदवार बेरोजगार हैं। और इस बेरोजगारी के चलते नशे की लत में फंसे युवाओं से कोई यह पूछने तक को तैयार नहीं है कि वे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हैं। नेता और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों से युवतियों को ऐसे अनैतिक धंधों में धकेलते हैं। क्या आज तक किसी ने ऐसी मजबूरी का शिकार शिक्षित युवतियों से पूछा है कि वे इस जाल में क्यों फंसी हुई हैं?

देश में नेताओं की वजह से अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की जाती हैं। अगर युवाओं को समय पर काम, नौकरी और रोजगार मिल जाए, तो वे ऐसे धंधों में क्यों पड़ जाते हैं?

NEET परीक्षार्थियों के लिए वडोदरा मंडल द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में सम्मलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा तथा सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिए वडोदरा, आणंद एवं भरूच स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन हेल्प डेस्कों पर तैनात रेलकर्मी ट्रेन कनेक्टिविटी, स्पेशल ट्रेनों एवं अन्य आवश्यक जानकारी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। परिक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ के मद्देनज़र वडोदरा में 3 तथा आणंद, गोधरा, भरुच एवं खेड़ा/नडियाद में 1 -1 अतिरिक्त यू टी एस काउंटर खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त स्टेशनों पर वाणिज्य एवं कार्मिक विभाग के कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की विशेष तैनाती की जा रही है। तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना प्रसार तथा यात्री सहायता कार्यों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर समय-समय पर सार्वजनिक उद्घोषणाएँ (Announcements) एवं यात्री सूचना प्रसारित की जाएंगी, जिससे परीक्षार्थियों एवं उनके साथ आने वाले अभिभावकों का सुरक्षित, व्यवस्थित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित,कुछ ट्रेनें छायापुरी, बाजवा, विश्वामित्री स्टेशन से शार्ट टर्मिनेट/ शार्ट ओरिजनेट

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में वडोदरा स्टेशन पर ब्लॉक के अंतर्गत वडोदरा स्टेशन यार्ड में यार्ड रीमॉडलिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य हेतु TWO व नॉन इंटरलॉकिंग (NI) कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत कार्य हेतु ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु कुछ ट्रेनों का टर्मिनेशन एवं ओरिजिनेशन अस्थायी रूप से विश्वामित्री (VS), बाजवा (BJW), छायापुरी (CYI), प्रतापनगर (PRTN) एवं मकरपुरा (MPR)स्टेशनों पर किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्य के अंतर्गत वडोदरा स्टेशन पर दिनांक 21 जून, 2026 से 08 जुलाई, 2026 तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी।

इस महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है :

शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन ट्रेनें :-

1. ट्रेन संख्या 19819 वडोदरा–कोटा एक्सप्रेस दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 19820 कोटा–वडोदरा एक्सप्रेस दिनांक 20 जून, 2026 से दिनांक 07 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 19036 अहमदाबाद–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
4. ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
5. ट्रेन संख्या 69233 वडोदरा–दाहोद मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।

6. ट्रेन संख्या 69117 वडोदरा–दाहोद मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
7. ट्रेन संख्या 69119 वडोदरा–दाहोद मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
8. ट्रेन संख्या 69121 वडोदरा–गोधरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–छायापुरी के बीच निरस्त रहेगी।
9. ट्रेन संख्या 69101 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
10. ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
11. ट्रेन संख्या 69113 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
12. ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।

13 ट्रेन संख्या 69109 सूरत–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

14. ट्रेन संख्या 69111 सूरत–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
15. ट्रेन संख्या 69122 गोधरा–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
16. ट्रेन संख्या 69120 दाहोद–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
17. ट्रेन संख्या 69118 गोधरा–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
18. ट्रेन संख्या 69234 दाहोद–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा छायापुरी–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
19. ट्रेन संख्या 69114 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
20. ट्रेन संख्या 69108 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
21. ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
22. ट्रेन संख्या 12930 वडोदरा–वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शाम 16:45 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा स्टेशन पर 17:05/17:10 तक 5 मिनट स्टॉपेज होगा।
23. ट्रेन संख्या 59049 वलसाड–वडोदरा पैसेंजर ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक मकरपुरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा मकरपुरा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
24. ट्रेन संख्या 59050 वडोदरा–वलसाड पैसेंजर ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक मकरपुरा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजनेट की जाएगी तथा वडोदरा-मकरपुरा के बीच निरस्त रहेगी।

25 ट्रेन संख्या 59549 वडोदरा–वटवा पैसेंजर ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक प्रतापनगर स्टेशन से सुबह 5:40 बजे शॉर्ट ओरिजनेट की जाएगी तथा वडोदरा स्टेशन पर 06:25/06:30 तक 5 मिनट का ठहराव होगा। एवं यह ट्रेन 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 को पूर्णतः निरस्त रहेगी

26. ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच निरस्त रहेगी।
27. ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा पैसेंजर ट्रेन दिनांक 21 जून, 2026 से दिनांक 08 जुलाई, 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा बाजवा-वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में सफाई अभियान में सहभागी हुए : स्वयं कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया

▸▸ स्वच्छता केवल बाह्य सफाई नहीं, बल्कि एक जीवनशैली एवं संस्कार है : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी

▸▸ ग्रामीणजन-युवा तंबाकू, गुटखा, पानमसाले का सेवन पूर्णतः बंदकर पौष्टिक भोजन लें; निर्व्यसनी तथा संस्कारवान बनकर गाँव, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएँ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में सफाई अभियान में सहभागी हुए और उन्होंने ग्रामीणजनों के साथ झाड़ू से स्वयं कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहा कि स्वच्छता केवल बाह्य सफाई नहीं है, बल्कि एक जीवनशैली एवं संस्कार है। स्वच्छ भारत राष्ट्र निर्माण की नींव है। 'जहाँ स्वच्छता, वहाँ स्वास्थ्य'; इस न्याय से स्वच्छता से समाज स्वस्थ बनेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक का अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखकर 'स्वच्छता ही सेवा' के मंत्र को चरितार्थ करने तथा समृद्ध व गौरवशाली भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देने का आह्वान किया और प्राकृतिक खेती का महत्व बताते हुए उपस्थित ग्रामीणजनों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने आछवणी गाँव स्वच्छ और सुगठित बने, गाँव में भाईचारा, सद्भाव, एकता बने रहें; इसके लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छता को स्वभाव बनाने तथा खुले में शौच जाने वाले ग्रामीणजनों के लिए देशव्यापी स्वच्छता आंदोलन चलाया और आज देश के करोड़ों घर शौचालय से युक्त बने हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आछवणी गाँव स्वच्छ एवं सुगठित बने; इसके लिए सभी मिलकर स्वच्छता को प्राथमिकता दें। ग्रामीणजनों को सचेत करते हुए कहा कि ग्रामीणजन तथा विशेष रूप से युवा तंबाकू, गुटखा, पानमसाले का सेवन पूर्णतः बंदकर पौष्टिक भोजन लें तथा निर्व्यसनी और संस्कारवान बनकर गाँव, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएँ। विकास तथा समृद्धि की आकांक्षा ही 'विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047' के गुजरात के विजन को साकार करने में सहायक होगी।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गाँव के दो स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, पदाधिकारी-अधिकारी, स्थानीय अग्रणी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन जुड़े।

पश्चिम रेलवे में पहली बार वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड को मिला प्रतिष्ठित CII "GreenCo GOLD" रेटिंग सम्मान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को पर्यावरणीय उत्कृष्टता और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) – ग्रीन बिजनेस सेंटर (GBC) द्वारा प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 जून 2026 को आयोजित 15वें GreenCo Summit 2026 में वरिष्ठ मण्डल मेकेनिकल इंजीनियर वटवा, श्री अशोक कुमार को प्रदान किया। इस उपलब्धि के साथ वटवा शेड देश के अग्रणी हरित एवं सतत संस्थानों में शामिल हो गया है।

मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम),अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने कहा कि "इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को प्राप्त प्रतिष्ठित CII GreenCo GOLD Rating पूरे अहमदाबाद मंडल और पश्चिम रेलवे के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। वटवा शेड ने नवाचार, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर यह सिद्ध किया है कि उत्कृष्ट परिचालन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।"

"भारतीय रेल वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड की यह सफलता भारतीय रेल की अन्य इकाइयों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी तथा हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।"

पश्चिम रेलवे में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक लोको शेड को यह प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating प्राप्त हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की अग्रणी भूमिका को दर्शाती है।

GreenCo Rating भारत की अपनी तरह की पहली ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है, जो किसी संस्थान के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करती है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण एवं पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, हरित अवसंरचना एवं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय नवाचार जैसे विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। GOLD Rating इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।

ऊर्जा दक्षता एवं स्वच्छ ट्रैक्शन

इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा ने डीजल आधारित परिचालन से पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर परिवर्तन करते हुए वर्ष 2022-23 में 1.88 करोड़ लीटर से अधिक डीजल (HSD) की खपत को शून्य पर ला दिया, जिससे Scope-1 उत्सर्जन में लगभग 100 प्रतिशत की कमी आई। प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग हेतु असेंबली बे में लॉन्ग-ट्यूब डेलाइट हार्वेस्टिंग (Brillantor) प्रणाली स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त पारंपरिक पंखों के स्थान पर 5-स्टार रेटेड BLDC पंखे, CFL एवं हैलोजन लाइटों के स्थान पर LED लाइटें, ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर का उपयोग कर ऊर्जा बचत सुनिश्चित की गई।

जल संरक्षण की दिशा में नवाचार

वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 20.5 लाख लीटर जल पुनर्भरण की क्षमता विकसित की गई है। लोकोमोटिव के विंडशील्ड वॉशर सिस्टम में अभिनव संशोधन तथा जलरहित यूरिनल की व्यवस्था के माध्यम से जल संरक्षण एवं लोको पायलटों की स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट जल एवं उपचारित जल के निष्कासन को शून्य तक लाते हुए ताजे जल की विशिष्ट खपत में निरंतर कमी दर्ज की गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

अहमदाबाद मंडल में लगभग 1,863 किलोवाट पीक (kWp) क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष अनुमानित 24.22 लाख यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त वटवा शेड के लिए समर्पित रूफटॉप सौर परियोजना भी प्रस्तावित है। इससे भारतीय रेल के वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को बल मिल रहा है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

Scope-1, Scope-2 तथा Scope-3 के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में निरंतर वर्ष-दर-वर्ष कमी दर्ज की गई है। 800 से अधिक जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से कार्बन ऑफसेट को भी बढ़ावा दिया गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामग्री संरक्षण

"Zero Waste to Landfill" दृष्टिकोण अपनाते हुए स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अधिकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण तथा ISO 14001 एवं ISO 50001 प्रमाणित प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। वार्षिक औसत खपत (AAC) की समीक्षा एवं पुर्जों के पुनः उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की गई है।

हरित आपूर्ति श्रृंखला एवं नवाचार

ग्रीन प्रमाणित विक्रेताओं से खरीद, पैकेजिंग में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा पैकिंग अपशिष्ट वापसी जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।

'गरवी गुर्जरी' ने वोकल फॉर लोकल के विजन को दिया वेग : पाँच वर्षों में 123 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री

▸▸ 2025-26 में 43.07 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री के साथ रचा गया इतिहास, गुजरात की समृद्ध हथकरघा-हस्तकला विरासत को मिली नई ऊँचाई

▸▸ कारीगरों को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ रहा है 'गरवी गुर्जरी' मंच

गांधीनगर : गुजरात के हथकरघा एवं हस्तकला उत्पाद केवल वस्तुएँ नहीं हैं; बल्कि राज्य की संस्कृति, सृजनात्मकता तथा कारीगरों के कौशल का जीवंत प्रतिबिंब हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार परंपरागत कलाओं को नई पहचान, व्यापक बाजार और आर्थिक शक्ति प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इन प्रयासों में गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम (जीएसएचएचडीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित 'गरवी गुर्जरी' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गरवी गुर्जरी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने 53 वर्षों के इतिहास में पहली बार 43.07 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बिक्री दर्ज कर नया इतिहास रचा है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े देखें, तो कुल 123.88 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री कर गरवी गुर्जरी ने गुजरात के हथकरघा एवं हस्तकला क्षेत्र को नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। इसमें वर्ष 2021-22 में 11.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 12.00 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में 25.20 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 32.09 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 में 43.07 करोड़ रुपए की बिक्री शामिल है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि परंपरागत कला को उचित दिशा, सुदृढ़ नीति तथा आधुनिक बाजार का सहयोग मिले, तो वह आर्थिक विकास का सशक्त आधार बन सकती है। यह सफलता केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, अपितु हजारों कारीगरों के आत्मविश्वास, कौशल एवं परिश्रम की भी सशक्त अभिव्यक्ति है।

देश-विदेश तक पहुँचा ब्रांड, कारीगरों को आर्थिक बल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में गरवी गुर्जरी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने साथ जुड़े हुए लगभग 8 हजार कारीगरों से 16.01 करोड़ रुपए के उत्पादों की खरीद कर उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक बल प्रदान किया है। राज्य व राज्य के बाहर संचालित 22 एम्पोरियमों द्वारा 20.77 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि देश-विदेश में आयोजित विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों द्वारा 22.30 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि गरवी गुर्जरी अब केवल एक क्षेत्रीय ब्रांड नहीं, बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की कला एवं हस्तकला की पहचान बन रही है।

कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयास

राज्य सरकार ने कारीगरों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही; मार्केटिंग के लिए अधिक अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी कला को उचित मूल्य एवं व्यापक पहचान मिल सके। ये प्रयास परंपरागत कला को आधुनिक जीवनशैली तथा वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

गरवी गुर्जरी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने परंपरागत कला को केवल संरक्षित करने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे आधुनिक आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुसार ढालकर उसकी उपयोगिता तथा मांग; दोनों में वृद्धि की है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को समान अवसर मिलने से उनकी आय में वृद्धि हुई है और उनके जीवनस्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है।

अगले वर्ष अत्याधुनिक प्रशिक्षण और नए बाजारों पर बल

वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार एवं निगम ने और महत्वाकांक्षी आयोजन किया है। इसके तहत कारीगरों को अत्याधुनिक टेक्निकल प्रशिक्षण देना, नए एवं आकर्षक उत्पाद विकसित करना, उत्पादों की व्यापक खरीद सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मेलों में अधिक भागीदारी द्वारा नए बाजारों तक पहुँच बनाना जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य कारीगरों की आय, रोजगार एवं सामाजिक सम्मान में निरंतर वृद्धि करना है।

धर्मिष्ठाबेन चुडासमा के उत्पादों को मिली देशव्यापी पहचान

अहमदाबाद की कढ़ाई-बुनाई (एम्ब्रॉइडरी) कारीगर धर्मिष्ठाबेन चुडासमा कहती हैं कि वे कई वर्षों से गरवी गुर्जरी से जुड़ी हुई हैं। पहले उनके उत्पादों की बिक्री केवल स्थानीय स्तर पर ही होती थी, परंतु गरवी गुर्जरी द्वारा आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिलने से उनकी कला गुजरात के अलावा देश के विभिन्न राज्यों तक पहुँची है।

वे कहती हैं कि गरवी गुर्जरी द्वारा उनके उत्पादों की खरीद कर देशभर के एम्पोरियमों में बिक्री की जाती है, जो उनके लिए गौरव की बात है। प्रदर्शनियों के दौरान कला-प्रेमी उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क होने से उन्हें कस्टमाइज ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

कारीगरों के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत गरवी गुर्जरी

गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम लिमिटेड, गांधीनगर के एक अधिकारी ने कहा कि गरवी गुर्जरी लगातार कारीगरों के उत्थान के लिए कार्यरत है। उत्पादों की खरीद, मार्केटिंग सहायता तथा प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कर कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही; कौशल विकास प्रशिक्षण और डिजाइन विकास कार्यशालाओं द्वारा कारीगरों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार सशक्त बनाया जा रहा है। गरवी गुर्जरी गुजरात के प्रतिभाशाली कारीगरों की आजीविका को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गरवी गुर्जरी आज केवल एक ब्रांड नहीं है; बल्कि गुजरात की समृद्ध कला, संस्कृति तथा कारीगरों की प्रतिभा का सशक्त प्रतीक बन गई है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों, मजबूत नेतृत्व और कारीगरों के अविरत परिश्रम के समन्वय से गुजरात ने सिद्ध किया है कि 'विकास भी, विरासत भी' केवल एक मंत्र नहीं; बल्कि विरासत के संरक्षण के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने का सफल मॉडल भी है।

नवसारी जिले के पाणीखडक गाँव के प्राथमिक विद्यालय में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का रात्रि विश्राम

▸▸ राज्यपाल ने सुबह-सुबह विद्यार्थियों के साथ किया योग एवं प्राणायाम

▸▸ विद्यार्थी स्वस्थ एवं तेजस्वी भविष्य के लिए दैनिक जीवन में योग तथा प्राणायाम को अवश्य स्थान दें : राज्यपाल

▸▸ योग सत्र में राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ विभिन्न योग एवं प्राणायाम का प्रायोगिक अभ्यास कर उसके स्वास्थ्योन्मुखी महत्व के विषय में प्रेरक संवाद किया

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव में प्राथमिक विद्यालय के साधारण वर्ग खंड (क्लासरूम) में सादगीपूर्ण रात्रि विश्राम किया। उदित हो रहे प्रातःकाल में राज्यपाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों, ग्रामीणजनों तथा युवाओं के साथ योगाभ्यास किया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के गाँव के अतिथि बनकर ग्रामीण कल्याण के ध्येय के साथ विद्यालय में रात्रि निवास करने के इस प्रेरक दृष्टिकोण से ग्रामीणजनों तथा विद्यालय के स्कूली बच्चों में भारी उत्साह और आनंद का वातावरण देखने को मिला।

सुबह-सुबह (तड़के) आयोजित विशेष योग सत्र में राज्यपाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ विभिन्न योगासन किए और बच्चों को योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन एकाग्र बनता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के व्यस्त एवं आधुनिक जीवन में योग तथा प्राणायाम स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि योग द्वारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव दूर होता है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी अधिक एकाग्रता प्राप्त होती है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका तथा मन की शांति एवं ध्यान केन्द्रित करने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम का प्रायोगिक अभ्यास किया और उससे श्वसन तंत्र के मजबूत बनने की वैज्ञानिक समझ दी।

राज्यपाल ने बच्चों के साथ अत्यंत स्नेहपूर्वक संवाद साधते हुए उनके अध्ययन, दैनिक गतिविधियों तथा कॅरियर के बारे में मार्गदर्शन दिया और जीवन में अनुशासन, परिश्रम तथा सकारात्मक विचारधारा अपनाकर उत्तम शिक्षा के साथ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए आशीर्वचन दिया। पवित्र गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यह योग सत्र संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धरती माता को हरियाली करने के संकल्प के रूप में दिए गए अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' अंतर्गत राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी के आदिजाति क्षेत्र आछवणी में वृक्षारोपण किया

▸▸ समग्र राज्य में 'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' में 8 करोड़ पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य

▸▸ हरियाला गाँव तथा ई-पर्यावरण अंतर्गत आछवणी में विभिन्न 28 प्रजातियों के 1600 पेड़-पौधों का रोपण एवं संरक्षण होगा

▸▸ राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री का नवसारी के आदिजाति गाँवों में रात्रि प्रवास

▸▸ ग्रामसभा में ग्रामीणजनों के साथ संवाद, सामूहिक सफाई तथा प्राकृतिक खेती परिसंवाद

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी जिले के आदिजाति क्षेत्र आछवणी में गुरुवार को 'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' अंतर्गत ग्रामीणजनों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागी हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती माता को हरियाली बनाने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने का आह्वान किया है और प्रत्येक व्यक्ति से 'एक पेड़ माँ के नाम' अंतर्गत अपनी माता की स्मृति में एक वृक्ष लगाने की अपील की है।

प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू कराए गए इस देशव्यापी अभियान के दो चरण पूर्ण हुए हैं और इस वर्ष 'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' अंतर्गत गुजरात ने 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

इस अभियान के प्रथम चरण में वर्ष 2024 में गुजरात ने 17.50 करोड़ पौधों तथा वर्ष 2025 में दूसरे चरण में 10.96 करोड़ पौधों का रोपण कर अग्रसरता प्राप्त की है।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार शाम नवसारी की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में ग्रामीणजनों के सहयोग से हरियाला गाँव एवं ई-पर्यावरण अंतर्गत वृक्षारोपण किया, जिसमें 'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' अभियान के तहत विभिन्न 28 प्रजातियों के 1600 पेड़-पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाएगा।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने इस वृक्षारोपण के अतिरिक्त; नवसारी जिले के आदिजाति गाँवों आछवणी एवं पाणीखडक में गुरुवार को रात्रि निवास कर ग्रामसभा में ग्रामीणजनों के साथ संवाद, सामूहिक सफाई और प्राकृतिक खेती के विषय में संवाद-वार्तालाप किया।

'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' अभियान अंतर्गत वन विभाग ने नवसारी जिले में समग्रतः 42.34 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। नवसारी जिले ने वर्ष 2025-26 में 'एक पेड़ माँ के नाम-2.0' अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 20.38 लाख पौधों का रोपण किया था।

-: राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी :-

इस अवसर पर ग्रामीणजनों को प्रेरित करते हुए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी ने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के इस युग में यदि हमें हमारी धरती माता को बचाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा।

उन्होंने रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खेती में प्राकृतिक पद्धतियाँ अपनाने से ही जमीन की उर्वरकता तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की सराहना करते हुए ग्रामीणजनों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और लगाए गए वृक्षों का संतान की तरह जतन करने का आह्वान किया। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि पानी की एक-एक बूंद का संग्रह तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा पर्यावरण जतन के लिए उठाया गया एक छोटा कदम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण स्तर से प्रारंभ हुई यह जनजागृति ही सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण की नींव बनेगी।

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रकृति के जतन व संवर्धन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे, तो ही हम अपने जीवन तथा संस्कृति को सुरक्षित रख सकेंगे। कोरोना काल के मुश्किल समय की याद दिलाते हुए उन्होंने जोड़ा कि प्रकृति ने मानव जाति को एक बड़ा सबक सिखाया है कि चाहे कितना भी धन या वैभव होगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा और किसी का कुछ नहीं चलेगा।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नागरिकों से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने पानी और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूक होने की अपील करके जल संचय के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य में अधिक से अधिक तालाब बनें और वे पानी से भरें; इसके लिए हम सभी के सामूहिक प्रयास होने चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण संरक्षण के अभियानों में जन-जन को जोड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक का अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने और उसका संरक्षण करने का प्रेरक आह्वान किया।

इस अवसर पर नवसारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, परियोजना प्रशासक श्री स्वप्निल एम. सिसले, वन उप संरक्षक सुश्री उर्वशी प्रजापति, पदाधिकारी-अधिकारी, स्थानीय अग्रणी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सादगी खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव के साधारण किसान के घर लिया रात्रि भोजन

किसान परिवार के आतिथ्य तथा देसी भोजन का आनंद उठाया

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोटोकॉल को परे रखते हुए नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव के पटेल फळिया (मोहल्ले) में रहने वाले साधारण किसान जितेन्द्रभाई चुनीलाल देसाई के लीपाई वाले घर में जमीन पर बैठकर रात्रि भोजन लिया। उन्होंने हरे-भरे खेतों तथा सर्पाकार रास्तों के बीच स्थित इस छोटे-से घर में 1 वर्षीय बेटी 11 वर्षीय निक्की के हर्ष-उमंग के बीच तथा देसाई परिवार के सभी सदस्यों के साथ काँसे की थाली-प्याली में परोसे गए देसी नागली-चावल के रोटले (बड़ी रोटी), खिचडी, कढी और मिक्स सब्जी का स्वाद लिया।

इस अवसर पर दोनों महानुभावों ने समाज में यह प्रेरणादायी संदेश दिया कि जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, वैसे ही सत्ता एवं पद के बीच भी नम्रता बनाए रखना ही वास्तविक महानता है। सच्ची भव्यता सादगी में है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने अत्यंत शांत एवं आतिथ्यपूर्ण वातावरण में भोजन करके सामान्य परिवार के आतिथ्य का सम्मान कर आम जनता के प्रतिनिधि होने की प्रतीति कराई।

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु लिए जा रहे मेजर ब्लॉक के कारण 21 जून, 2026 से 08 जुलाई, 2026 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

21 जून, 2026 से 08 जुलाई, 2026 तक निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें

- ▸▸ ट्रेन संख्या 19036 अहमदाबाद–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के आंशिक बीच निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69114 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69108 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें

- ▸▸ ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69101 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69113 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त आंशिक रहेगी।
- ▸▸ ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त आंशिक रहेगी।

प्रारंभिक स्टेशन में परिवर्तिन

- ▸▸ ट्रेन संख्या 59549 वडोदरा–वटवा मेमू वडोदरा के स्थान पर प्रतापनगर स्टेशन से 05.40 बजे प्रस्थान करेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा आरंभ करे। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

जून-2026 का मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा

23 से 25 जून के दौरान आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव के कारण राज्य स्तरीय 'स्वागत' के आयोजन में बदलाव

गांधीनगर, : राज्य के नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री का स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा।

राज्य में 23 से 25 जून के दौरान आयोजित होने जा रहे शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के चलते जून-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम गुरुवार के बजाय सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा।

इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' के लिए अभ्यावेदक सोमवार, 22 जून, 2026 की सुबह 8 से 11 बजे के दौरान अपना अभ्यावेदन मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमवार, 22 जून को दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निवारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे।